



NAGAR NIGAM GREATER JAIPUR


(Pd. Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015,Raj.INDIA).

ई- निविदा NIB No-01-DC.(A.M.)/NNGJ/2024-25/156

02-08-24

tender issuing form

S.No.	Item	Yearly rate contract for Particulars	
1-	Name of work	नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र से मृत पशु उठाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिगोनिया में निस्तारित करने का कार्य मय संसाधन व श्रमिक के वर्ष 2024-25 एक वर्ष हेतु संविदा पर करवाये जाने के लिए	
2-	Cost of tender document (non refundable)in favor of municipal corporation jaipur payable at jaipur	Rs. 1000/-	
3-	RISL processing fee (non refundable) in favor of managing director RISL payable at jaipur	Rs. 5000/-	
4-	Estimated project cost	Rs. 1.60 cr	
5-	Earnest money deposit (2%)	Rs. 3,20,000/-	
6-	Tender publication on official web site. http://eproc.rajasthan.gov.in .	02-08-2024	03.00 PM
7-	Tender download start date	02-08-2024	03.00 PM
8-	Pre bid meeting	08-08-2024	11.00 AM
9-	Bid submission start date	09-08-2024	10.00 AM
10-	Bid submission End date	13-08-2024	02.00 PM
11-	Technical bid opening date/time	13-08-2024	03.00 PM


Deputy Commissioner
(Animal Management)
Nagar Nigam greater Jaipur

JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Pd. Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015,Raj.INDIA).

ई- निविदा NIB No- 01--/DC.(A.M.)/NNJG/2024-25

TECHNICAL - BID

(PART-I)

Bid Document Issued to:

M/s. _____

Bid Security Fee Rs. :.....Deposited by online

Dated :.....

(Details of Bid Security to be filled by bidder)

Note :

1. Bidder should deposit tender fee EMD and RISL processing fees online to the Website www.jaipurmc.org before submission date and time and tender will be accept valid after above receipt scanned copy will be uploaded to the www.eproc.rajasthan.gov.in Sales tax Clearance & registration certificate is also to be scanned.
2. Complete Bid Document shall be submitted by the bidder duly filled and signed on each page accompanied with requisite relevant enclosure in a sealed envelope indicating clearly name & address of agency/firm and Name of work.
3. bidder shall submit Undertaking & affidavit on stamp paper of Rs. 100.
4. Incomplete document shall be rejected, without assigning any reason thereof.
5. Envelope "A" should contain duly filled Formats "A" & "B"
6. The entrepreneur should read the INSTRUCTIONS TO BIDDERS carefully before submitting the tender.

Signature & Seal

**(Firms Authorized Person)
With Name, Date & Seal**

Deputy Commissioner

(Animal Management)

Nagar Nigam Greater Jaipur



JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Pd. Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015,Raj.INDIA).


ई- निविदा NIB No- 01-/DC.(A.M.)/NNGJ/2024-25

Bid issuing form

S.No.	Item	Yearly rate contract for Particulars
1-	Description of Job	नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र से मृत पशु उठाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिगोनिया में निस्तारित करने का कार्य मय संसाधन व श्रमिक के वर्ष 2024-25 एक वर्ष हेतु संविदा पर करवाये जाने के लिए
2-	Approaximate cost of Job	Rs. 1.60 cr
3-	NIB No.	01-/DC.(A.M.)/NNGJ/2024-25
4-	Bidding document fee.	Rs. 5000/-
5-	Bid security	Rs. 3,20,000 /- (2% of Approaximate cost of Job)
6-	Last Date of Selling Bid	-----
7-	Last Date of receipt of Bid	Before 2.00 PM Date <u>13-08-24</u>
8-	Issued to	M/s.----- ----- -----
	(To be filled by issuing officer)	
9	Bid fee received date	

Note:- Bidder should deposit tender fees, EMD and RISL processing fees online to the website www.jaipurmc.org. before submission date and time and tender will be accept valid after above receipt scanned copy will be uploaded to the www.eproc.rajasthan.gov.in. sales tax clearance & registration certificate is also to be scanned.

WWW.JAIPURMC.ORG
WWW.SPPP.RAJ.NIC.IN


Deputy Commissioner
(Animal Management)
Nagar Nigam greater Jaipur



JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Pd. Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015,Raj.INDIA).

ई-निविदा NIB No 01-DC.(A.M.)/NNGJ/2024-25

Technical Bid


S.No	Discription	Discription of Documents deposit by tenderar
1-	Description of Job	नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र से मृत पशु उठवाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में निस्तारित करने का कार्य मय संसाधन व श्रमिक के वर्ष 2024-25 एक वर्ष हेतु संविदा पर करवाये जाने के लिए
2-	Name of Firm	
3-	Address & Mob No. of Firm	
4-	Email ID of firm	
5-	PAN No. of firm	
6-	Registration No. to ESI Department.	
7-	Registration No of PF Department.	
8-	Firm deposit affidavit about firm is not black listed & No financial liabilities are due against firm.	
9-	2% Bid security	
10-	Bidding Document fee. Rs. 5000 (Non Refundable)	
11-	RISL Processing fees Rs. 1000 (Non Refundable)	

Note:-

- 1- Bidder should deposit Bidding document fees, Bid Security and RISL processing fees online to the website www.jaipurmc.org. before submission date and time and tender will be accept valid after above receipt scanned copy will be uploaded to the www.eproc.rajasthan.gov.in. sales tax clearance & registration certificate is also to be scanned.
- 2- Above Mention Information are Correct according to my Knowledge & Faith and over firm are agree for all trem & rules of the tender.

WWW.JAIPURMC.ORG
WWW.SPPP.RAJ.NIC.IN

Signature of tenderar
with firm seal


उपायुक्त (पशु प्रबधन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर



JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Pd. Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015,Raj.INDIA).

TECHNICAL- BID

- (1) Entrepreneurs shall read carefully before filling up all the information in the format "A"
- (2) There should be no discrepancy in the information given in format "A" otherwise tender is liable to be rejected without seeking clarification on account of submission of false Undertaking.

FORMAT 'A'

1. GENERAL INFORMATION

S. No.	Item	Details	S. No. of Annexure
1.	Name of the bidding Organization:		
	Address :		
	Fax :		
	Phone :		
	E-mail :		
2.	Name & Details of Key Persons		

c	Item	Details	S. No. of Annexure
3.	Type of Organization & Structure of Organization		
(A)	(Proprietary/ Partnership/ Pvt. Ltd./ Public Ltd./ Jt. Venture.)		
(B)	Structure of Organization (enclosed details)		
(C)	Registration Certificate (attach document)		
5.	Details of fee.		
(A)	Document Fee Online		
(B)	Bid Security Online		
6.	Details of Black Listing.		
7.	Is your organization clear from tax liabilities? Latest Income Tax & Sales Tax Clearance Certificate duly verified by C.A. should be attached.		

Note:

1. Attachments are to be enclosed to show documentary evidence. In absence of which any information submitted by the bidder is liable to be considered as incomplete and Bid may not be considered for evaluation.

Signature & Seal

(Firms Authorized Person

With Name & Designation)



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन लाल कोठी, टोंक रोड जयपुर)

NIB No--01--/DC.(A.M)/NNGJ/2024-25

मृत मवेशी के निस्तारण की शर्त निविदा वर्ष 2024-25

1. नगर निगम जयपुर ग्रेटर सीमा से मृत पशुओं को उठाकर निगम प्रशासन द्वारा बताये गये चिहन्त स्थान पर निस्तारण के कार्य हेतु एक वर्ष के लिए तकनीकी व वित्तीय बिड की ई-प्रोक्यूर्मेंट सिस्टम द्वारा आमंत्रण की जाती है।
2. पैनल में सम्मिलित सभी फर्मों द्वारा बिड सिक्योरिटी राशि कुल बिड राशि की 02 प्रतिशत जमा करानी होगी। कार्यादेश उपरान्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी कार्य आवंटन के प्रतिशत के हिसाब से कुल राशि की 05 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।
3. संवेदक को मृत पशु की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् 2.30 घण्टे की समयावधि एवं विशेष परिस्थिति में 3 घण्टे (जो उपायुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी) के अन्तराल में मौके से मृत पशु उठाना होगा। ऐसा नही करते पाये जाने पर प्रति शिकायत 1000/- रु. की शास्ती संवेदक पर प्रति घण्टा (निर्धारित समय के उपरान्त अतिरिक्त समय पर) आरोपित की जा सकेगी।
4. संवेदक को कार्यादेश उपरान्त मृत पशु की शिकायत प्राप्त करने से लेकर मृत पशु निस्तारण के कार्य को नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये गये निम्न प्रफोर्मा के अन्तर्गत रिकॉर्ड संधारित करना होगा।

प्रथम पंजिका

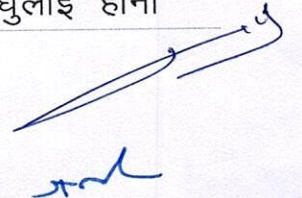
दिनांक	क्रं. सं.	शिकायत सं.	शिकायतकर्ता का नाम/पता	शिकायत दर्ज करने का समय	मृत पशु का प्रकार	शिकायत निस्तारण में प्रयुक्त वाहन	शिकायत निस्तारण में प्रयुक्त स्टाफ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

द्वितीय पंजिका

दिनांक	क्रं. सं.	शिकायत सं.	शिकायत निस्तारण का समय	मृत पशु का प्रकार	हिंगोनिया पहुंचाने का समय	प्रयुक्त वाहन व स्टाफ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त पंजिका व बिल्लियां नगर निगम ग्रेटर जयपुर के मृत पशु निस्तारण –प्रभारी एवं प्रभारी अधिकारी (पशु चिकित्सा अधिकारी) द्वारा प्रमाणित होगी व राजकीय दस्तावेज समझा जावेगा परन्तु इसको नियमित रूप से रखरखाव संवेदक को करना होगा, साथ ही प्रभारी को उक्त रजिस्टर प्रतिदिन प्रमाणित करना होगा। उपायुक्त पशु प्रबंधन द्वारा मांग करने पर अथवा प्रतिमाह संवेदक को उक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।

5. संवेदक द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्षेत्र से मृत पशु उठाने के कार्य में वाहन व श्रमिकों की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान स्वयं संवेदक को करना होगा।
6. मृत पशु उठाने के कार्य में प्रयुक्त श्रमिक :-
 - a) प्रत्येक वाहन पर कम से कम 06 श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। कम श्रमिक उपलब्ध करवाने पर प्रति श्रमिक 500 रु. प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जावेगी।
 - b) प्रत्येक वाहन पर कार्यरत श्रमिक मय मास्क, हेलमेट गमबूट रात्री में रेडियम जाकेट पहने होना आवश्यक होगा। उक्त संसाधन श्रमिक के पास उपलब्ध नहीं होने पर 500 रु. प्रति श्रमिक प्रतिदिन शास्ति आरोपित की जावेगी।
 - c) प्रत्येक वाहन पर कार्यरत श्रमिकों एवं ड्राइवर की ड्रेस पर उसकी नेम प्लेट लगी होना आवश्यक है।
 - d) प्रत्येक वाहन पर कार्यरत श्रमिक मद्यपान नशे में पाए जाने पर संवेदक पर रु. 1000/-प्रति श्रमिक शास्ति आरोपित की जा सकेगी व श्रमिक को कार्य से हटाते हुए संवेदक को तुरन्त दूसरा श्रमिक कार्य पर नियुक्त करना होगा।
 - e) उक्त कार्य में नियुक्त किए गए सभी श्रमिकों का संवेदक को दुर्घटना बीमा करवाना होगा। इसके अभाव में किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर नगर निगम ग्रेटर किसी प्रकार से आर्थिक भार वहन नहीं करेगा और ना ही नगर निगम ग्रेटर जयपुर की जिम्मेदाररी होगी।
7. पशु परिवहन वाहन :- सफल संवेदकों को मृत पशु निस्तारण हेतु कम से कम 05 वाहन + 1 JCB + 1 क्रेन हर समय उपलब्ध रखने होंगे।
 - a) वाहन में रखा गया मृत पशु बाहर से दिखाई नहीं देना चाहिए। वाहन बन्द बाँडी के होंगे।
 - b) वाहन के दोनो तरफ मृत पशु परिहवन-अनुबंधित नगर निगम ग्रेटर जयपुर, ड्राइवर का नाम, कन्ट्रोल रूम दबावखाना, प्रभारी/प्रभारी अधिकारी का नाम मय मोबाईल न0 अंकित होना चाहिए
 - c) वाहन स्वच्छ रखना होगा, वाहन की सेनेटाईजर से नियमित धुलाई होना



आवश्यक है।

- d) वाहन पर स्पष्ट अंकित करना होगा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा निःशुल्क सेवा साथ ही संवेदक उक्त स्लोगन को कपड़े, तिरपाल आदि से ढकेगा नहीं।
- e) वाहनों की पार्किंग पुरानी कोतवाली दबावखाना अथवा नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।
- f) वाहन पर सभी आर.टी.ओ. नियम लागू होंगे व यातायात विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- g) प्रत्येक वाहन पर **GPS** लगाना होगा जिसका रिकार्ड उपायुक्त पशु प्रबंधन/प्रभारी अधिकारी (पशु चिकित्सा अधिकारी)/प्रभारी को बिल के साथ उपलब्ध करवाना होगा।
- h) संवेदक को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- i) वाहनों का रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम होना चाहिये या 500 रु. के स्टाम्प पर किराये पर लेने (जिस फर्म के पास वाहन हो से) का अनुबंध आवश्यक है, संलग्न करना होगा।

उक्तानुसार वाहन का उपयोग नहीं करने पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा संवेदक पर 5000/-रु. प्रतिदिन की प्रति वाहन शास्ति आरोपित की जावेगी एवं लगातार एक सप्ताह तक शास्ति आरोपित होने पर ठेका निरस्त कर ठेकेदार की सभी निगम में जमा सभी राशियां जब्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

8. संवेदक को वित्तीय बिड में सभी करो सहित दर प्रति पशु (गौवंश, भैंसवंश, ऊँट, घोडा, गधा, हाथी इत्यादि) की प्रस्तुत करनी होगी।
9. संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा मृत पशु के शिकायतकर्ता से मृत पशु उठाने के बदले में किसी भी प्रकार से इनाम, भोजन या अन्य प्रकार से राशि की मांग किया जाना भ्रष्टाचार की परिभाषा में मानते हुए संवेदक पर अपराध साबित होने पर नियमानुसार धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है या प्रति शिकायत ली गई राशि के अतिरिक्त 10,000/- रुपये शास्ती भी आरोपित की जा सकती है।
10. संवेदक द्वारा मृत पशु उठाने में किसी प्रकार की असमर्थ होने पर मृत पशु के निस्तारण में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में अन्य फर्मों से कार्य कराने या बाजार या निगम द्वारा किए जाने पर वास्तविक व्यय की वसूली संवेदक से की जावेगी। इसके कारण किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था भंग होती है, तो इसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. फर्म संवेदक द्वारा कार्य बंद किया जाता है तो शर्त सं0 03 के अतिरिक्त 10000 रु प्रतिदिन शास्ती आरोपित की जावेगी तथा 24 घण्टों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो फर्म का कार्यादेश निरस्त कर ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही की

जावेगी।

12. कार्य में प्रयुक्त सभी श्रमिकों के भुगतान व अन्य सुविधाओं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी इनका पालन संवेदक को करना होगा। इस संबंध में नगर निगम, ग्रेटर जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा।
13. उक्त निविदा प्रथम कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा सन्तोषजनक कार्य होने पर एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा (1+1) इसके अतिरिक्त संवेदक का कार्य सन्तोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमती से **RTPP Act 2012 & Rules 2013** के अनुसार निविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
14. संवेदक को समय-समय पर राज्य सरकार व निगम द्वारा जनहितार्थ जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी व आपदा प्रबंधन के समय मृत पशुओं से उत्पन्न समस्या के निस्तारण हेतु निर्धारित शर्तों के पार भी व्यवस्था सुनिश्चित कर जन हानि रोकने को तत्पर रहना होगा।
15. निविदा में भाग लेने वाली फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए इस आशय का शपथ पत्र 50 रु. के स्टाम्प पर देना अनिवार्य है।
16. संवेदक को माह की 10 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिदिन 1000/- रूपये की शास्ती आरोपित की जावेगी।
17. संवेदक द्वारा श्रमिकों/मानव संसाधनों को आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।
18. निविदादाता को अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत राशि के बराबर का गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का सन्तोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें किये गये कार्य की राशि अंकित होनी चाहिए।
19. फर्म का टर्नओवर विगत 03 वर्षों का औसत कुल निविदा राशि के 50% राशि के बराबर होना आवश्यक है।
20. संवेदक को कार्यादेश देने के पश्चात 24 घण्टे के अंदर तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम दरदाता स्वीकृत फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ न करने पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मों से निविदा में स्वीकृत न्यूनतम दर पर सहमति उपरान्त कार्य कराने हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर स्वतंत्र होगा। इन फर्मों द्वारा कार्य न करने पर स्वीकृत दर पर बाजार से व अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अन्य फर्मों से कार्य कराने पर होने वाले व्यय से दोगुना राशि शास्ती के बतौर संवेदक से वसूल की जा सकेगी या निगम द्वारा किए जाने पर वास्तविक व्यय की वसूली की जावेगी।
21. राज्य सरकार एवं निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना निविदादाता को करनी होगी।
22. अनुमानित (**Estimated**) दर से कम दर डालने वाली फर्म/संवेदक से अन्तर

- राशि (At par की दर से जितनी कम है) (Work per formance Guarantee) के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व (As per RTPP Act Rules 2013 के नियम 75 (A)) निगम कोष में जमा करनी होगी। उक्त राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात लौटा दी जावेगी।
23. निविदा दाताओं को निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेगिंग फीस ऑनलाईन नगर निगम, जयपुर वेबसाईट WWW.jaipurmc.org.in. Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके WWW.eproc.rajasthan.gov.in or www.sppp.raj.nic.in. पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
 24. निविदा की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में एक सेटलमेन्ट कमेटी का गठन किया जावेगा जिसमें श्रीमान आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में निदेशक विधि, वित्तीय सलाहकर, उपायुक्त पशु प्रबन्धन सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव विवादित प्रकरण को सेटलमेन्ट कमेटी के समक्ष संवेदक से विवादित बिन्दु के संबंध में पत्र प्राप्त होने के 20 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। सेटलमेन्ट कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों (नगर निगम ग्रेटर जयपुर/फर्म) को मान्य होगा।
 25. निविदादाता को ई.पी.एफ, ई.एस.आई, GST में पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, संवेदक को प्रतिमाह सभी संबंधित श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. राशि नियमानुसार जमा करवाकर बिल के साथ रसीद प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में श्रमिकों के द्वारा प्राप्त शिकायत या निगम को ज्ञात होने पर पीएफ/एसआई की राशि संवेदक के बिल से काटकर जमा करायी जा सकती है।
 26. नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा निविदा पूर्ण होने तक किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर स्वतंत्र होगा।
 27. बिडर द्वारा रखी गई किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी।
 28. निविदा प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं तत्संबंधी नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधान लागू होंगे।
 29. संवेदक द्वारा निविदा शर्तों की पूर्ण पालना नहीं करने पर उसे नोटिस दिया जायेगा तीन नोटिस उपरान्त कार्य निविदा शर्तों अनुसार नहीं करने पर निविदा को निरस्त करते हुए फर्म/संवेदक के खिलाफ नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
 30. श्रमिकों की चोट या दुर्घटना की स्थिति में, सभी जिम्मेदारियां और खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ना ही निगम किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु बाध्य होगा।
 31. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिये कोई भी पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।




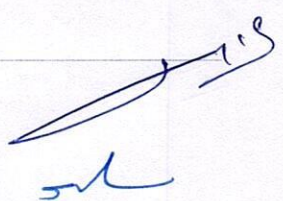
2

5

12

11

32. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान होंगे।
33. किसी भी न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर न्यायालय होगा।
34. संवेदक तत्कालीन प्रवर्तित श्रम कानून एवं नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
35. नियोजित श्रमिकों को समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करना होगा निगम इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
36. संवेदक को कार्य संबंधित समस्त सुरक्षा कोड नियमों का पालन करना होगा।
37. नगर निगम में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी का करीबी रिश्तेदार निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जावेगा।
38. सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी सेवानिवृत्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि तक बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के नगर निगम की निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित रहेगा।
39. संवेदक की मृत्यु की दशा में संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर शेष रहा कार्य विधिक वारिस बिना किसी पेनल्टी के पूर्ण कर सकेंगा।
40. संवेदक से वसूली योग्य राशि उसके द्वारा जमा परफोरमेन्स सिक्क्योरिटी से या उसके किसी बिल से की जा सकेगी। यदि पूरी राशि वसूली नहीं हो सके तो पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली की जा सकेगी।
41. मृत पशु निस्तारण में उपयोग लिये जाने वाले वाहन का विवरण (मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नं., बीमा इत्यादि) उपलब्ध करवाना होगा।
42. जी.पी.एस डिवाइस तथा विशेष प्रकार के वाहन ड्राइवर की मैपिंग करवाना होगा।
43. जी.पी.एस डिवाइस लगवाने के साथ (प्रदर्शित) **display** सुविधा एवं जी.आई.एस मैप के साथ उपलब्ध करवाना होगा।
44. जी.पी.एस वाहन का **identification map** के साथ **color coded** होना अनिवार्य होगा।
45. प्रत्येक वाहन को जोनवाईज, वार्डवाईज, के साथ वाहन नं. देखने की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा।
46. वाहन सं. के हिसाब से **route map** पर (प्रदर्शित) **display** होना तथा जी.ओ. टैगिंग ऐप पर **location @ longitude and latitude app** और उसी समय मृत पशु की फोटो अपलोड करना होगा।
47. संवेदक के वाहन द्वारा उठाये गये मृत पशु की जानकारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये गये **GEO tagging app** में दर्ज करनी होगी जिससे गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य होगा।

48. संवेदक को प्रस्तुत बिलो का भुगतान नगर निगम ग्रेटर जयपुर के कॉल सेन्टर पर दर्ज शिकायत अनुसार किया जाएगा।
49. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग बोर्ड कॉरपोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड/डी बार अथवा डीफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए इस संबध में 100 रू. नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र निविदा के साथ सलंगन किया जाना आवश्यक है।
50. संवेदक द्वारा संलग्न **annexure A,B,C,D, व E,** पर हस्ताक्षर कर **upload** किया जाना अनिवार्य है।

पशु चिकित्सा अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

वरिष्ठ लेखाधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

उपायुक्त—मुख्यालय
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

उपायुक्त पशु प्रबंधन
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

वित्तीय सलाहकार
नगर निगम ग्रेटर जयपुर



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन लाल कोठी, टोंक रोड जयपुर)

NIB.No. -01/DC.(A.M)/NNGJ/2024-25

Financial-Bid (दर-अनुसूची)

कार्य का नाम	दर प्रति मृत पशु
नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र से मृत पशुओ को मौके से उठवाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिगोनिया में निस्तारण करने का कार्य मय संसाधन व श्रमिक के वर्ष 2024-25 एक वर्ष हेतु कार्य करवाये जाने के लिए	शब्दों में रू. अंको में रू.

निविदादाता

उपायुक्त (पशु प्रबंधन)
उपायुक्त (पशु प्रबंधन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal Noof
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an
affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Doc1

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall not be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

- (b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.
- (c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.
- (d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.
- (e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors,
- (f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

- (a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.
- (b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.
- (c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code

The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:

Near Relatives barred from tendering

The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared in valid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control

The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:

The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.